Government have also seen an interview given by the former Deputy Prime Minister to the Illustrated Weekly of India of 29th July, 1990 in which he has been quoted as suggesting that one of the Cabinet Ministers was, involved in the Bofors deal. The Prime Minister thereupon, requested the then Deputy Prime Minister to substantiate his allegations, pointing out that he had not done so in respect of his earlier allegations as well, so far. The former Deputy Prime Minister has not substantiated his charges.

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की रुग्णता का रोका जाना

1564. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी उद्यम ब्यूरो से सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की बढ़ती रुग्णता को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए कहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ब्यूरो से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस योजना बनाई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाऊ गोबर्धन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रुग्णता का अध्ययन करना एक सतत प्रक्रिया है जो सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा सरकारी उद्यम विभाग के परामर्श से किया जाता है उनके पुनर्स्थापित/पुनः सक्रिय करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा अलग-अलग उद्यम के आधार पर अपेक्षित उपाय शुरु किये जाते हैं।

निरक्षरों की बढ़ती संख्या

1565. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विगत पंद्रह वर्षों में निरक्षरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : देश में साक्षरता के आंकड़े दशाब्दिक जनगणना अभियानों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं। 1981 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार देश में सभी आयु वर्गों में कुल निरक्षरों की संख्या 42,42,56,000 थी। 1991 में अगली जनगणना के बाद ही इस समय निरक्षरों की संख्या का पता चलेगा।

देश में संस्थानों विश्वविद्यालयों, द्वारा संचालित अवैध पाठयक्रम

1566. **श्रीमती वीणा वर्मा :**

श्री कपिल वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में अनेक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे अनेक पाठयक्रमों को अवैध होना पाया है और लोगों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने और उनके द्वारा भ्रमित किये जाने के प्रति सावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सूची क्या है और वे कब से चल रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसे संस्थानों और विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे संस्थानों में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और सरकार द्वारा ऐसे